छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
ग्यारहवां सत्र

श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 19 फरवरी, 2007

माननीय सदस्यगण,

छत्तीसगढ़ राज्य की इस गरिमामय विधानसभा में, आप सबके बीच पहली बार आकर में बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। वर्ष 2007 के इस पहले अधिवेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं की जो मजबूत बुनियाद रखी है, उस पर राज्य के विकास की शानदार इमारत बन रही है।

2. यह गौरव और संतोष का विषय है कि मेरी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों की जरूरतों पर, वनवासियों तथा कमजोर तबकों की बेहतरी पर ज्यादा ध्यान देने की नीति अपनाई है। वास्तव में सबको साथ लेकर और बुनियादी जरूरतें पूरी करके ही राज्य के विकास का बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

3. किसानों को गरीबी की तकलीफों से निजात दिलाने के लिए मेरी सरकार ने उन्हें खेती को लाभप्रद बनाने की सुविधाएं और साधन प्रदान करने का कार्य, एक अभियान के रूप में प्रारम्भ किया। इसके तहत कृषि ऋण की दरों में कमी करने का एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। पहले चरण में एक अक्टूबर, 2004 से नौ प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। फिर एक और साहसिक निर्णय लेकर वर्ष 2006–2007 में किसानों को सात प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई। इस तरह की पहल करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव छत्तीसगढ़ को मिला।

4. चालू वर्ष में सरकार ने जगदलपुर और बिलासपुर बैकों को तीस करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। मेरी सरकार ने कृषि ऋण सुलभ कराने के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित वैद्यनाथन समिति की मुख्य सिफारिश स्वीकार कर ली हैं। इससे हानि में चल रहे चार जिला बैंक और चार सौ सत्ताइस प्राथमिक साख समितियां पुनर्जीवित हो सकेंगी। इन उपायों से किसानों को फसल ऋण की सुविधा में व्यापक विस्तार होगा।

5. इस वर्ष बयालीस हजार आठ सौ हेक्टेयर क्षेत्र के लिए स्प्रिंकलर एवं पन्द्रह हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ड्रिप सिस्टम वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सामान्य नलकूप योजना में देय अनुदान की राषि अठारह हजार रूपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये की गई है।

6. लाभदायी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मक्का, दलहन तथा तिलहन के रकबों में वृद्धि करने और फसलीय क्षेत्रों का विस्तार करने के साथ–साथ उद्यानिकी के रकबे में विस्तार पर जोर दिया गया है। वर्ष 2006–2007 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनाओं के अंतर्गत फलों के लगभग छिहत्तर हजार हेक्टेयर, सब्जियों के एक लाख छियानवे हजार हेक्टेयर, मसालों के उनतीस हजार हेक्टेयर, फूलों के सोलह सौ हेक्टेयर तथा औषधी एवं सुगंधित फसलों के सोलह सौ हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है।

7. मेरी सरकार ने पशुपालन को किसानों और अन्य कमजोर तबकों की पूरक आय का जरिया बनाने की रणनीति अपनाई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क गाय एवं बैल जोड़ी उपलब्ध कराने की योजना के तहत चौदह हजार से अधिक गायों एवं छब्बीस हजार से अधिक बैलजोड़ी का वितरण किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र में राज्य गठन के समय अस्सी हजार मीट्रिक टन उत्पादन के विरूद्ध अब एक लाख इकतीस हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। मछली बीज के मामले में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है। यह सिलसिला निरंतर बढ़ाया जाएगा।

8. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस वर्ष सरकार ने पैंतीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की है। धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ का पंजाब के बाद देश में दूसरा स्थान है। धान खरीदी व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप इस वर्ष धान खरीदी से होने वाली हानि लगभग समाप्त हो गई है।

9. अपने पूर्व निर्णय पर अमल करते हुए मेरी सरकार द्वारा पहुंच विहीन एवं खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में दो सौ बांसठ ग्रेन बैकों की स्थापना की गई है, जिनमें नौ हजार नौ सौ सैंतालीस हितग्राहियों को दस हजार दो सौ अस्सी क्विंटल चावल वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक हजार छः सौ बयालीस नए ग्रामीण ग्रेन बैंकों की स्थापना की जा रही है।

10. मेरी सरकार राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने की चुनौती से अवगत है। विगत तीन वर्षों में सिंचाई प्रतिशत को सत्ताइस प्रतिशत से बढ़ाकर तीस प्रतिशत के करीब लाया गया है। वर्ष दो हजार चार में सिंचाई नलकूपों की संख्या पिचानवें हजार थी। तीन वर्ष की कालावधि में ही छियालीस हजार सिंचाई नलकूप निर्मित किए गए हैं। जिनसे पैंसठ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लघुसिंचाई में आया है।

11. वर्तमान में पांच वृहद, बारह मध्यम एवं छः सौ इक्यावन लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनसे लगभग चार लाख दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, निर्मित होगी। सरकार ने जहां एक ओर वर्षों से लंबित पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का काम शुरू किया है, वहीं नई सिंचाई परियोजनाओं के चयन में आदिवासी बहुल क्षेत्रों सरगुजा, जशपुर, बस्तर तथा दन्तेवाड़ा का विशेष ध्यान रखा है।

12. मेरी सरकार ने खरीफ सिंचाई के बाद जलाशयों में उपलब्ध जल को ग्रीष्मकालीन धान के एक लाख तीस हजार हेक्टयेर क्षेत्र में सिंचाई हेतु देने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। इससे किसानों को अतिरिक्त धान एवं पशु–चारा उपलब्ध होने के साथ ही तेरह लाख बाईस हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।

13. मेरी सरकार ने नदियों पर एक हजार छः सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से पांच सौ पन्चानवे एनीकट बनाने की योजना शुरू की है जिससे पचासी हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इनमें से सैंतीस एनीकट बनाए जा चुके हैं तथा छियासठ एनीकट निर्माणाधीन हैं।

14. मेरी सरकार ने सिंचाई की जल दर में वृद्धि न करते हुए केवल औद्योगिक जल दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य में जल प्रबंधन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ''सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006'' पारित कराया गया और जल उपभोक्ता संथाओं के चुनाव संपन्न कराए गये हैं।

15. मेरी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामवासी को प्रतिदिन कम से कम चालीस लीटर शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। प्रदेश में करीब अट्ठासी प्रतिशत बसाहटों में यह कार्य पूरा हो गया है। शेष बची बसाहटों में पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य में पहली बार दो हजार से अधिक आबादी वाले दो सौ साठ ग्रामों में नल–जल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की इक्यानवे प्रतिशत शालाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष शालाओं में इस वर्ष शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

16. उनतीस नगरीय निकायों में नल–जल परियोजनाएं प्रगतिरत हैं तथा शेष उनचास नगरीय निकायों की परियोजनाएं भी बना ली गई हैं। रायपुर नगर के लिए मंजूर तीन सौ तीन करोड़ रूपये की योजना का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा।

17. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पांच सौ करोड़ रूपये लागत की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगामी दो वर्षों में दस लाख शौचालय निर्मित किये जाएंगे इनमें से अभी तक दो लाख साठ हजार से अधिक परिवारों हेतु शौचालय निर्मित किये जा चुके हैं।

18. गांवों की बेहतरी के लिए मेरी सरकार ने अधोसंरचना विकास, रोजगार और पंचायत राज व्यवस्था की मजबूती को मूलमंत्र माना है। मेरी सरकार ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला पंचायतों के लिए भवन निर्माण एवं उन्नयन के काम को प्राथमिकता देगी।

19. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत सत्रह लाख अट्ठासी हजार सात सौ पैंतालीस परिवारों का पंजीयन कर उन्हें 'परिवार रोजगार कार्ड' प्रदान किया गया है। अब तक मांग के आधार पर आठ लाख चौंसठ हजार से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और तीन सौ बयासी लाख, बत्तीस हजार मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। योजना के तहत लगभग दस हजार कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं और छः हजार तीन सौ से अधिक कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा 'ग्राम उत्कर्ष योजना' भी प्रारम्भ की गई है।

20. राज्य में परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दुकानें बनाकर धोबी एवं नाई का परंपरागत कार्य करने वाले बी.पी.एल. हितग्राहियों को आबंटित करने का निर्णय किया गया है जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

21. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। विगत वर्ष चार सौ छियालीस करोड़ रूपये की लागत से दो हजार किलोमीटर डामरीकृत सड़कें पूर्ण की गई हैं। वहीं इस वर्ष तीन हजार पांच सौ किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।

22. मेरी सरकार ने अच्छी सड़कों को विकास की रफ्तार बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया माना है चालू वित्तीय वर्ष में चार हजार सात सौ किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया गया है। तिरानवे पुलों का निर्माण पूरा हुआ और दो सौ इकहत्तर कार्य प्रगति पर हैं। छः कॉरीडोर सड़कों का निर्माण दो हजार छियासी किलोमीटर तक पूर्ण किया गया है।

23. ए.डी.बी. से एक हजार छः सौ किलोमीटर सड़कों के उन्नयन हेतु एक हजार दो सौ छियासी करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कराई गई है। प्रथम चरण में सात सौ चार किलोमीटर के सात मार्गों का कार्य प्रारम्भ किया गया है और दूसरे चरण में सात सौ किलोमीटर सड़कों की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वहीं नाबार्ड, केन्द्रीय सड़क निधि ऋण, राष्ट्रीय राजमार्ग, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत मिली मंजूरी आदि मदों से भी अनेक कार्य पूर्ण कराए गए हैं।

24. सुगम एवं बाधारहित यातायात के लिए दो रेल्वे ओव्हर ब्रिज पूर्ण किए गए हैं तथा एक दर्जन रेल्वे ओव्हर ब्रिजों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सात बाईपास मार्गों का निर्माण शुरू किया गया है तथा बारह बाईपास मार्गों का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा। रायपुर–दुर्ग फोरलेन का कार्य पूर्ण किया गया है तथा रायपुर से आरंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है। रायपुर से बिलासपुर और रायपुर से धमतरी मार्ग को भी फोरलेन में परिवर्तित करने की योजना है। विकास की गति बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने प्राइवेट पार्टनर के साथ संयुक्त कम्पनी का गठन किया है। इस योजना के अंतर्गत चौहद सौ करोड़ रूपये की लागत से एक हजार पांच सौ किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

25. मेरी सरकार ने शहरों की अधोसंरचना के विकास एवं शहरों के योजनाबद्ध विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्ष 2006–2007 में गौरव पथ के रूप में सभी नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त मुख्य सड़कों की स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरों की मुख्य समस्या गंदे पानी के निकास के लिए हर नगरीय निकाय में ड्रेनेज की योजना स्वीकृत की गई है।

26. शहरों में सुविधाजनक अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड, उन्मुक्त खेल मैदान, ज्ञान स्थली, पुष्प वाटिका, सरोवर–धरोहर जैसी राज्य प्रवर्तित योजनाओं को भी और अधिक बढ़ाया गया है। इनमें शत प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अनुदान के रूप में दी जा रही है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत योजनाओं की स्वीकृति के लिए त्वरित पहल की गई है।

27. गांवों में शहरी सुविधाएं विकसित करने की गई अवधारणा 'पुरा' परियोजना की शुरूआत करने में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसके तहत तहसील के बाईस गांवों के लिए पहली 'पुरा' परियोजना प्रारंभ की गई है।

28. मेरी सरकार राज्य में 'आवास क्रांति' का सपना साकार कर रही है। निम्न आय वर्ग के निवासियों को सुविधाजनक और सुरक्षित ढंग से रियायती दरों पर मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दस हजार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटित किया जा चुका है और दस हजार भवनों के निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है। बीपीएल परिवारों के लिए अटल आवास योजना के तहत पांच हजार भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

29. 'नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी' द्वारा नया रायपुर ''उप नगर''बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए ग्रामीणों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अर्जित की जा रही है। कैपिटल कॉम्पलेक्स के तहत शासकीय कार्यालयों के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा।

30. विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ओर जहां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वृहद बिजलीघर स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्युत मण्डल पांच सौ मेगावाट की कोरबा पूर्व परियोजना की दोनों इकाइयों में अगस्त,2007 तक उत्पादन प्रारम्भ करने की तैयारी में है। कोरबा पश्चिम में लगभग पांच सौ मेगावाट क्षमता की दो इकाईयों तथा सरगुजा जिले के प्रेमनगर में एक हजार मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का कार्य भी इस वर्ष प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोरबा दक्षिण में एक हजार मेगावाट, भैयाथान में पन्द्रह सौ मेगावाट तथा मड़वा में एक हजार मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

31. किसानों को सिंचाई पम्पों के लिए एक लाख नए कनेक्शन देने के अभियान के तहत छियालीस हजार से अधिक नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बस्तर, कांकेर,दंतेवाड़ा,कोरिया,सरगुजा जिलों में अप्रैल,2007 से ऑन डिमाण्ड तत्काल पम्प कनेक्शन दिए जाएंगे।

32. मेरी सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले आठ लाख पचार हजार एकलबत्ती कनेक्शनधारियों को निःशुल्क बिजली प्रदाय की जा रही है। साथ ही आठ लाख एकलबत्ती उपभोक्ताओं की चौदह करोड़ रूपये से अधिक बकाया राशि माफ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

33. 'अटल ज्योति योजना' के तहत छत्तीस गांवों और तीन हजार पम्पों के लिए अलग–अलग फीडरों से विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की जा चुकी है और एक सौ तीन गांवों और छः हजार आठ सौ चालीस पम्पों को अलग–अलग फीडरों से बिजली देने का कार्य प्रगति पर है।

34. मेरी सरकार ने गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में बायोडीजल उत्पादन के लिए अभिनव पहल की और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। वृहद् पैमाने पर बायोडीजल उत्पादन के लिए विगत दो वर्षों में इक्कीस करोड़ रतनजोत के पौधे लगाए जा चुके हैं और इस काम को जारी रखा जाएगा।

35. राज्य में शहरों से लेकर गांवों तक सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाएं पहुंचाकर सूचना क्रांति का नया युग प्रारम्भ करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। सुदूर अंचलों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क(स्वान) का कार्य प्रारम्भ हो गया है इस नेटवर्क से गांवों तक वैश्विक स्तर का ज्ञान आसानी से पहुंचेगा।

36. रायपुर नगर में संचालित चॉइस परियोजना की सफलता को देखते हुए इसे पांच नए जिलों दुर्ग, राजनांदगांव,बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर में शुरू किया जा रहा है राज्य में तीन हजार पांच सौ सामान्य सेवा केन्द्र प्रारम्भ किए जा रहे हैं जिनसे शहरों की तरह, सुदूर गांवों में भी ई–गवर्नेन्स सेवाएं, शासकीय जानकारियां एवं दस्तावेज त्वरित गति से लोगों को दिए जा सकेंगे।

37. विभिन्न शासकीय विभागों में निविदा प्रक्रिया को सरल तथा पारदर्शी बनाने हेतु राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे श्रम, समय एवं धनराशि की बचत होगी, निविदाकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण शासकीय विभागों को ई–प्रशासन रोड मैप भी तैयार कराया गया है।

38. किसानों और आम जनता को भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां सुगमता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। 'कम्प्यूटर ई–बस्ता' योजना के तहत पटवारियों को एक हजार पांच सौ अठहत्तर कम्प्यूटर–सह–उपकरण 'ई–बस्ते' के रूप में दिए जा चुके हैं। चार सौ बांसठ पटवारियों के रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

39. राज्य के हीरा,सोना जैस बेशकीमती खनिजों की खोज के लिए पहले से स्वीकृत टोही परमिटों के अतिरिक्त सात हजार पांच सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पांच टोही परमिट स्वीकृत किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2006–2007 में लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूनापत्थर तथा डोलोमाइट के नए भण्डार चिन्हित किए गए हैं।

40. राज्य की स्पंज आयरन/स्टील इकाइयों को एन.एम.डी.सी. द्वारा इस वर्ष बीस लाख टन लौह अयस्क का आवंटन दिया गया, जिसे आगामी वर्ष में बढ़ाने के लिए पहल की गई है। इस्पात/स्पंज आयरन इकाइयों की लौह अयस्क की आवश्यकता की दीर्घकालीन सुनिश्चित आपूर्ति व्यवस्था करने के लिए तीन सौ पचास मिलियन टन रिजर्व वाले बैलाडीला डिपाजिट–तेरह से लौह अयस्क का खनन एनएमडीसी तथा सीएमडीसी के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

41. मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इसके परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य रेल्वे द्वारा शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

42. मेरी सरकार की आकर्षक औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश तेजी से बढ़ा है। राज्य में औद्योगिक विकास की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। यह प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि जनवरी–अक्टूबर,2006 की अवधि में भारत सरकार के समक्ष इक्यासी हजार नौ सौ करोड़ रूपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और औद्योगिक निवेश प्रस्तावों में छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान रहा।

43. मेरी सरकार ने विशेष पिछड़े क्षेत्रों,अनुसूचित जनजाति बहुत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है जिससे निजी कंपनियों ने इन क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रभावी पहल की है। इससे विशेष पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर खुलेंगे।

44. राज्य में उल्लेखनीय औद्योगिक विकास के कारण भूमि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये चार जिलों में वृहद् औद्योगिक क्षेत्रों तथा आठ जिलों में लघु औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों की स्थापना हेतु निजी भूमि के अर्जन से प्रभावित परिवारों की, राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अनुरूप पुनर्वास व्यवस्था की जाएगी।

45. मेरी सरकार ने ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं, जिससे विभिन्न योजनाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा रहा है। पालितडाबा टसर ककून उत्पादन

का बीते वर्ष एक नया कीर्तिमान बनाया गया। दस हजार से अधिक हाथकरघा बुनकरों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए एक सौ चालीस बुनकर सहाकरी समितियों की साढ़े छह करोड़ रूपये से लगभग कर्ज राशि माफ करने का निर्णय लिया गया। नक्सल प्रभावित करीब एक हजार लोगों को टाटपट्टी, कम्बल, गणवेश आदि बनाने के कार्यों से जोड़ा गया है। हस्तशिल्प विकास के लिए रायपुर में विपणन सुविधा के लिए 'छत्तीसगढ़ हाट' की स्थापना की जा रही है।

46. मेरी सरकार ने श्रमिक विवादों के सुगम निराकरण के लिए औद्योगिक न्यायालय छत्तीसगढ़ की एक खण्डपीठ बिलासपुर में स्थापित की है तथा कोरबा जिले में श्रम न्यायालय की स्थापना की है। रायगढ़ में बड़ी संख्या में स्थापित हो रहे उद्योगों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निकट निगरानी हेतु वहां औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय की स्थापना की गई है।

47. मेरी सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राज्य में वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इन समितियों को वनों की सुरक्षा के एवज में काष्ठ एवं बांस से प्राप्त करीब पैंतीस करोड़ रूपये का भुगतान विगत वर्षों में किया गया है। इन समितियों को लाख पालन,रेशम कृमि पालन, मत्स्य पालन, बांस आधारित कुटीर उद्योग, दोना–पत्तल का निर्माण, लघु एवं औषधीय वनोपज का प्रसंस्करण आदि कार्यों में भी लगाया गया है। शहद प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ किया गया है और लाख उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम होने जा रहा है। पर्यावरण सम्मत औद्योगिक विकास का यह नया आयाम है।

48. तीन सौ छियानवे वनग्रामों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की दौड़ में अन्य ग्रामों के समकक्ष लाया जा रहा है। इसके तहत तीस करोड़ बहत्तर लाख रूपये व्यय कर बाईस हजार से अधिक कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रदेश के बिगड़े बांस वनों के पुनरूद्धार हेतु व्यापक बांस रोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बांस वनों के पुनरूद्धार से बांस उत्पादन बढ़ेगा जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के ऐसे और भी उपाय किए जाएंगे।

49. संग्रहण वर्ष 2005 के तेंदूपत्ता व्यापार के शुद्ध लाभ की सत्तर प्रतिषत राशि पच्चीस करोड़ छब्बीस लाख रूपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों में वितरण का कार्य प्रगति पर है। वर्श 2007 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर चार सौ पचास रूपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर पांच सौ रूपये की गई है जिससे इस वर्ष संग्राहकों को नब्बे करोड़ रूपये की मजदूरी मिलेगी। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के एक सदस्य को 'चरण पादुका' उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध जैव विविधता में औषधीय पौधों की पहचान, उपलब्धता, उपयोगिता एवं औषधी संबंधी विवरण का डाटाबेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था के सहयोग से तैयार किया गया है।

50. तेंदूपत्ता संग्राहकों को समूह बीमा योजना में तैंतीस लाख से अधिक संग्राहक बीमित हैं। इस योजना के स्थान पर जनश्री समूह बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नयी योजना के तहत संग्राहक की सामान्य मृत्यु की दशा में बीमा राशि वर्तमान तीन हजार पांच सौ से बढ़ाकर बीस हजार रूपये और दुर्घटना मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांग होने पर वर्तमान पच्चीस हजार रूपये से बढ़ाकर पचास हजार रूपये हो जाएगी।

51. मेरी सरकार द्वारा जन–स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए राज्य शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सफलता इसी बात से प्रमाणित है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित एस.आर.एस.डेटा के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो राज्य गठन के समय पन्चानवे प्रति हजार जीवित जन्म थी, वह घटकर राष्ट्रीय औसत चौंसठ से भी कम, इकसठ प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है। 17 अगस्त, 2006 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुपोषण, एनीमिया (रक्त अल्पता) जैसे सूचकांकों में काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। विगत तीन वर्षों में किए गए काम के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपस्वास्थ्य केन्द्रों के राष्ट्रीय मानदण्ड पूर्ण कर लिए है।

52. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का विस्ततार करने हेतु मेरी सरकार ने जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये 'धनवंतरी' सम्मान की स्थापना भी की गई है।

53. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के लिये प्रदेश में साठ हजार मितानिनों के द्वारा सेवाएं प्रदान करने की पहल कारगर रही है। इन्हें 'मुख्यमंत्री दवा पेटी' योजनांतर्गत दवा पेटी उपलब्ध करा दी गई है एवं उनकी सतत् प्रतिपूर्ति जारी है। प्रदेश में माता मृत्यु–दर कम करने तथा सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' लागू की गई है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन में जन–भागीदारी को बढ़ावा देने तथा अस्पतालों के काम–काज में सुधार लाने हेतु 'जीवनदीप अस्तपाल सुधार योजना' राज्य में लागू की गई है।

54. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विकास हेतु बहुआयामी और बहुस्तरीय पहल की है। इन प्रयासों का एक बड़ा लक्ष्य इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की योजनाओं द्वारा इन वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, वक्फ अधिकरण तथा वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त का गठन कर इन वर्गों के हित–संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

55. वर्ष 2006–2007 में एक सौ इकतीस पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में तथा इक्यासी हाईस्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इस वर्ष एक सौ नवीन प्री मैट्रिक छात्रावास, पच्चीस नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा एक सौ तेरह नवीन आश्रम शालाएं स्थापित की गई हैं।

56. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने निःशुल्क सायकल एवं गणवेश वितरण की योजना प्रमुखता से लागू की है। वर्ष 2006–2007 में करीब तीन लाख अट्ठाइस हजार छात्राओं को इसका लाभ मिला। छात्रावासी बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त छात्रावासों में विशेष शिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ तेरह हजार विद्यार्थियों को मिल रहा है। आठ सौ पैंतालीस ग्रामीण आदिवासी प्रतिभावान बच्चों को जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना के तहत उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आदर्श शिक्षक एवं आदर्श शाला पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई है। इन वर्गों के युवाओं को प्रशासनिक सेवा संबंधी परीक्षाओं से सफल बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण देने के लिए 'युवा कैरियर योजना' प्रारम्भ की गई है।

57. मेरी सरकार ने शिक्षा सुविधा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में नए महाविद्यालय तथा आईटीआई खोलने का निर्णय लिया। इसके तहत चालू वर्ष में अनुसूचित क्षेत्रों में छः नए महाविद्यालय तथा ग्यारह नए आईटीआई खोले गए हैं।

58. अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में 'मंगल भवनों' का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और फिलहाल तीन सौ पन्द्रह 'मंगल भवनों' का निर्माण जारी है। इसी तरह आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण हेतु एक हजार ग्राम देवता स्थलों 'देवगुड़ी' के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

59. मेरी सरकार ने 'स्कूल आ पढ़े बर जिन्दगी जा गढ़े बर' के आह्वान के साथ एक महाअभियान नए शिक्षण सत्र में प्रारम्भ किया था, जिससे शाला प्रवेश में बढ़ोतरी और ड्रॉप आऊट नियंत्रण में काफी सफलता मिली। इस वर्ष एक हजार चार सौ चौदह नवीन प्राथमिक विद्यालय, दो हजार पांच सौ अड़सठ नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक सौ सत्रह नवीन हाईस्कूल,उनसठ नवीन हायर सेकेण्डरी और पंद्रह नाइट शेल्टर स्कूल प्रारम्भ किए गए हैं। नक्सलवादी क्षेत्रों के लिए बावन कैंप शालाएं प्रारम्भ की गई हैं।

60. बीते एक साल में कुल सात हजार दो सौ पांच स्कूल भवनों एवं एक हजार सात सौ सत्ताइस अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे मेरी सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता झलकती है। साथ ही लगभग छियालीस लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें एवं अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बारह हजार दो सौ पच्चीस शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई है।

61. मेरी सरकार राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए तेरह महाविद्यालय भवनों का निर्माण प्रगति पर है और ग्यारह अन्य महाविद्यालय भवनों के निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है। सभी महाविद्यालयों में मरम्मत तथा अन्य सुविधाएं जुटाने के कार्य किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 'नेक' द्वारा कराया गया है। रायपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

62. रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्रह महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम दस महाविद्यालयों में 'एड ऑन' पाठ्यक्रम पहली बार लागू किया गया है। पांच महाविद्यालयों में ई–क्लास रूम की स्थापना की जा रही है। केन्द्रीय प्रयोगशाला बनाने का कार्य प्रारभ किया गया है। कोरबा में निजी सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है।

63. मेरी सरकार युवा शक्ति की रचनात्मक प्रतिभा निखारने को भी अपना जरूरी कर्त्तव्य मानती है। इस दिशा में सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिला एवं राज्य स्तर पर स्पोर्टस स्कॉलरशिप देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्गों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद राशि पुरस्कार के साथ–साथ खेल अलंकरण से भी सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, निःशक्तजन खेल प्रतियोगिता के खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा उत्सव में पदक प्राप्त करने वाले कलाकारों को नगद राशि पुरस्कार से सम्म्मानित किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। इससे युवाओं का उत्साह बढ़ा है।

64. छत्तीसगढ़ का नाम खेल जगत में रोशन करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना के निर्माण कार्य को गति प्रदान की है। राज्य में सिंथेटिक सतह के नए हॉकी स्टेडियम एवं खेल अकादमी के निर्माण का निर्णय लिया है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को निखार सकें। क्रीड़ा परिषद् बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

65. मेरी सरकार ने कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए बहुआयामी प्रयास आरम्भ किए जिससे महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों तथा समुदाय की सहभागिता से आंगनवाड़ी केन्द्रों को समुदाय के अपने केन्द्रों के रूप में संचालित कराने की पहल की गई। इसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वसहायता समूहों की देखरेख तथा उनके सहयोग से संचालित किया जा रहा है। समुदाय के सहयोग से बाल–भोज के आयोजन तथा 'गोद–भराई' की रस्म जैसे आयोजनों से कुपोषण के खिलाफ जनमत तैयार करने में हमें सफलता मिली है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुपोषण के स्तर में नौ प्रतिशत की गिरावट आई है, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है।

66. प्रदेश के निर्धन परिवारों को भी गर्व और आत्मसम्मान के साथ अपनी बेटी का विवाह सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा आरम्भ की गई 'छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना' को निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। व्यापक जनभागीदारी से इस योजना के जरिये अब तक साढ़े छः हजार निर्धन कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है।

67. मेरी सरकार पड़ोसी राज्यों में आने–जाने की सुविधा बढ़ाने के लिए अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु विशेष प्रयास कर रही है। इस दिशा में महाराष्ट्र राज्य के साथ अंतिम समझौता

सम्पन्न कर लिया गया है तथा आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश एवं झारखंड राज्यों के साथ प्रारम्भिक पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न कर लिया गया है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए वाहनों की पंजीयन पुस्तिका एवं चालक लायसेंस एक ही कार्ड पर जारी करने की व्यवस्था बनाई जा रही है।

68. मेरी सरकार ने चालू वर्ष में पांच नए न्यायिक जिले बनाए हैं। इससे राज्य के सभी सोलह जिले न्यायिक जिले बन गए हैं। इस वर्ष इक्कीस न्यायिक मजिस्ट्रेट लिंक न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं। पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण हेतु ग्यारह कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है। इकतीस फास्ट ट्रेक कोर्ट की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसे पुनः पांच वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। राज्य में तीन स्थाई लोक अदालतों की स्थापना की गई है। गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के अभियान में तेजी लाई जा रही है।

69. मेरी सरकार छत्तीसगढ़ की सर्वांगीण प्रगति के साथ ही संस्कृति के संरक्षण और विकास हेतु भी नए–नए उपाय कर रही है। परम्परा और संस्कृति के एक अनोखे संग्रहालय 'पुरखौती मुक्तांगन' के प्रथम चरण का लोकार्पण राज्य के छठवें स्थापना दिवस समारोह अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के करकमलों से सम्पन्न हुआ। रायपुर में बहुआयामी संस्कृति संस्थान और राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय की स्थापना हेतु कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है। महंत घासीदास संग्रहालय का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है।

70. मेरी सरकार ने राज्य धरोहरों से जुड़े प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने में भी सफलता अर्जित की है। अनेक प्रसिद्ध मेलों के लिए अधोसंरचना और आयोजनों के स्वरूप में विस्तार कर पर्यटन विकास से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में 'कुम्भ' मेला की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए राज्य का पहला मेला कानून बनाया गया। अन्य प्रमुख स्थानों को उनके महत्व के अनुसार संस्कृति और पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है पर्यटक ट्रेन चलाने की कार्यवाही भी प्रगति पर है। पर्यटन से जुड़े विभिन्न आयामों और उसके व्यावसायिक पहलुओं का सुनियोजित ढंग से विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में होटल मैनेजमेंट,कैटरिंग टैक्नालॉजी,एप्लाइड न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

71. साहसिक पर्यटक और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास हेतु मेरी सरकार ने 'कैलाश–मानसरोवर तीर्थ यात्रा आर्थिक सहायता नियम –2006' बनाए हैं। इनके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन–काल में प्रथम बार यात्रा करने पर पच्चीस हजार रूपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

72. मेरी सरकार ने एक ओर विकास योजनाओं के नवाचार और उपलब्धियों में कीर्तिमान बनाया है, वहीं वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में भी राज्य की उपलब्धियां सराहनीय रही हैं। मेरा मानना है कि इस कसावट से ही

जनहितकारी योजनाओं के अधिकाधिक संचालन की प्रेरणा और बल मिलता है। किसानों और अन्य जरूरतमंद तबकों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय अनुशासन का यह सिलसिला जारी रहना चाहिए।

73. मेरी सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से प्रदेश में नई कर प्रणाली ''वेट'' लागू की गई है। करदाताओं की सुविधा के लिए माह अक्टूबर, 2006 से कर संबंधी विवरणी पत्र तथा कर राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ''वेट'' के अंतर्गत ''ई–रिटर्न'' तथा ''ई–चालान'' सुविधा प्रारंभ करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।

74. आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रथम दायित्व होता है। इसके लिए पुलिस बल में वृद्धि आधुनिकीकरण और नए उपकरणों से सुरक्षा बलों को सुसज्जित करने हेतु मेरी सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। इस वर्ष पुलिस बल में दो भारत रक्षित वाहिनियों के गठन सहित छः हजार चार सौ तेईस नए पद स्वीकृत किए गए हैं। दो हजार पांच सौ से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से अधिकांश पद निर्माण तथा भर्तियां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में की गई हैं। प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए चन्द्रखुरी, रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है।

75. मैं मानता हूं कि नक्सलवादी हिंसा की चुनौती न सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बल्कि देश और लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। राज्य के वनवासी अंचलों में नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों के स्व–स्फूर्त शांति अभियान की मैं सराहना करता हूं। मेरी सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य की जनता ने नक्सलवादी हिंसा से निपटने के लिए जो सहमति बनाई है, वह भी सराहनीय है। इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक ओर जहां जन सहयोग और जनभागीदारी की जरूरत होती है वहीं दूसरी ओर सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। इस कड़ी में पुलिस तथा सशस्त्र बलों का मनोबल भी ऊंचा उठाना होगा। बस्तर ने नक्सल प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास एवं सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेरी कामना है कि इस बड़े कार्य में सभी दलों और जनता का सहयोग मेरी सरकार को मिले। वनवासियों तथा वन क्षेत्रों की बेहतर भूमिका और उनके ज्यादा योगदान से राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

76. आप सभी अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं पूर्ण करने में सफल हों और राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जाएं. इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़